

For Private Circulation Only



DEWAS UDYOG CIRCLE

Issue No – 421

Monthly Newsletter

June, 2024

President
Mr. Ashok Khandelia
Hon. Secretary
Mr. Anjan Shah



National Doctors Day



Inside pages.....

Knowledge Centre
Notifications/Circulars
Events
Attainments
Member's Corner
Sponsor's Page

World Population Day



ASSOCIATION OF INDUSTRIES DEWAS

1/B, 1/B/2 A, I. S. Gajra Industrial Area No. 1, A. B. Road, DEWAS (M.P.) Phone: (07272) 258052-53, 259455
E-mail : aidewas123@gmail.com, mail@aidewas.org Website : www.aidewas.org

KNOWLEDGE CENTRE*National Doctors Day*

All across India National Doctors' Day is celebrated on July 1 in memory of Dr. Bidhan Chandra Roy, physician and the second Chief Minister of West Bengal. He was born on July 1, 1882 and died on the same date in 1962.

Although supposed to be celebrated by [patients](#) in and benefactors of the [healthcare industry](#), it is usually celebrated by [health care organizations](#). Staff may organize a lunch for doctors during which physicians are presented with tokens of recognition. Historically, a card or red carnation may be sent to physicians and their spouses, along with a flower being placed on the graves of deceased [physicians](#).

World Population Day

World Population Day is an [annual event](#), observed on [July 11](#) every year, which seeks to raise awareness of [global population](#) issues. The event was established by the Governing Council of the [United Nations Development Programme](#) in 1989.

It was inspired by the [public interest](#) in Five Billion Day on July 11, 1987, the approximate date on which the world's population reached five billion people. World Population Day aims to increase people's [awareness](#) on various population issues such as the importance of [family planning](#), [gender equality](#), [poverty](#), [maternal health](#) and [human rights](#).

Important Days in July

July 1	Doctor's Day
July 2	World UFO Day
July 4	American Independence Day
July 7	International Day of Cooperatives
July 11	World Population Day
July 17	World Day for International Justice
July 18	Mandela Day
July 26	Kargil Victory Day
July 27	Central Reserve Police Force Foundation Day
July 28	World Hepatitis Day

“We cannot solve problems with the kind of thinking we employed when we came up with them.” — Albert Einstein

[NOTIFICATIONS/CIRCULARS](#)

रजिस्ट्री सं. सी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15062024-254723
CG-DL-E-15062024-254723

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 306]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 14, 2024/ज्येष्ठ 24, 1946

No. 306]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 14, 2024/JYAISHTHA 24, 1946

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2024

सा.का.नि. 329(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इस योजना का संक्षिप्त नाम कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2024 है।
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।
- कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में, पैरा 32क में उपपैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) जहाँ कोई नियोक्ता निधि में किसी अंशदान के संदाय में या अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) या धारा 17 की उपधारा (5) के अधीन उनके द्वारा अंतरित किए जाने वाले अपेक्षित संचयों के अंतरण में या अधिनियम या योजना के किसी अन्य उपबंध के अधीन या अधिनियम की धारा 17 के अधीन विनिर्दिष्ट किसी भी शर्त के अधीन देय किन्हीं प्रभारों के संदाय में चुक करता है, वहाँ केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या ऐसा अधिकारी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किया जाए, नियोक्ता से प्रतिमाह अंशदान के बकाया के एक प्रतिशत या उसके भाग की दर से नुकसानी वसूल कर सकेगा।"

[फा. सं. आर-15011/01/2022-एसएस-II]

आलोक मिश्रा, संयुक्त सचिव

3596 GI/2024

(1)

Cont'd to next page

“Learn as if you will live forever, live like you will die tomorrow.” — Mahatma Gandhi

NOTIFICATIONS/CIRCULARS

2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

टिप्पण : कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), संख्यांक का.नि.आ. 1506, तारीख 2 सितंबर, 1952 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 225(अ), तारीख 27 मार्च, 2020 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th June, 2024

G.S.R. 329(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, namely:—

1. Short title and Commencement.— (1) This Scheme may be called the Employees' Provident Funds (Amendment) Scheme, 2024.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, in paragraph 32A, for sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

"(1) Where an employer makes default in the payment of any contribution to the fund, or in the transfer of accumulations required to be transferred by him under sub-section (2) of section 15 or sub-section (5) of section 17 of the Act or in the payment of any charges payable under any other provisions of the Act or Scheme or under any of the conditions specified under section 17 of the Act, the Central Provident Fund Commissioner or such officer as may be authorised by the Central Government by notification in the Official Gazette in this behalf, may recover damages from the employer at the rate of one per cent. of the arrear of contribution per month or part thereof."

[F. No. R-15011/01/2022-SS-II]

ALOK MISHRA, Jt. Secy.

Note : The Employees' Provident Funds Scheme, 1952 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), vide number SRO. 1506 dated the 2nd September, 1952 and was last amended vide notification number G.S.R. 225(E), dated the 27th March, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR
JAISWAL

Digitally signed by
AMIT KUMAR JAISWAL
Date: 2024.06.15
13:32:16 +05'30'

“Stay away from those people who try to disparage your ambitions. Small minds will always do that, but great minds will give you a feeling that you can become great too.” — Mark Twain

NOTIFICATIONS/CIRCULARS

श्रमिकों को बढ़ी हुई मजदूरी मिलना हुई बंद

दिविजय ने सीएम को लेटर में लिखा मजदूरों की लड़ाई लड़ने के बजाय सरकार फैक्ट्री मालिकों के साथ खड़ी

रवंग दुनिया • मोकल

मार्च में प्रदेश सरकार ने श्रमिकों को मजदूरी की दरें बढ़ाकर 1 अप्रैल से लागू किए जाने का आदेश दिया था, लेकिन श्रमिकों

को मजदूरी की बढ़ी हुई दरें मिलती कि इस मामले में औद्योगिक संगठनों ने कोर्ट से स्टे ले लिए। अब श्रमिकों को बढ़ी हुई मजदूरी की दरों से राशि नहीं मिल रही है। इस पर पूर्व सीएम दिविजय सिंह ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखा है। दिविजय सिंह ने अपने पत्र में लिखा- दिनों दिन बढ़ती महंगाई के दौर में प्रदेश के लाखों श्रमिकों की मजदूरी में कमी किए जाने से प्रदेश के श्रमिक वर्ग में राज्य सरकार के प्रति घटी आक्रोश है। सरकार को न्यायलय में मजदूरों के हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। इसके स्थान पर राज्य शासन फैक्ट्री मालिकों के

साथ खड़ी दिखाई दे रही है। जिम्मेदार अफसरों का पत्र रख मजदूरों के शोषण की खुली छूट दे रहा है। दिविजय ने अपने पत्र में आगे लिखा- न्यूनतम मजदूरी की दरों का निर्धारण राज्य शासन ने 2014 में किया था। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अनुसार 2019 में कामगारों की दरें बढ़ाई जानी चाहिए थीं। लेकिन, कंपनी मालिकों के दबाव में राज्य शासन के अक्सर मजदूरी की दरों में वृद्धि करने की जगह खामीशी बातें करते रहे। दूसरी तरफ श्रमिक संगठन लगातार मजदूरी बढ़ाने की मांग करते रहे।



मई में ही मिली बढ़ी मजदूरी, उसके बाद लग गया स्टे

दिविजय सिंह ने अपने पत्र में लिखा-

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत नियमों को दस साल तक दरकिनार करने के बाद सरकार ने 1 अप्रैल 2024 से अकुरुशल, अर्द्धकुरुशल, कुरुशल और उच्च कुरुशल श्रेणियों के श्रमिकों की दरों में क्रमशः वृद्धि कर दी। मई में प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों स्थित शासकीय दफ्तरी एवं अन्य निर्माण कार्यों में शामिल लाखों श्रमिकों को बढ़ी हुई मजदूरी मिल गई। दस साल बाद मित्त न्याय एक माह भी खुशियां खी दे सका और श्रम विभाग की अधिसूचना के विरोध में औद्योगिक संगठनों ने कोर्ट में याचिका दायर कर स्टे ले लिए।

सरकार ने कोर्ट में नहीं किया मजदूरों के हित में प्रयास

दिविजय सिंह ने पत्र में लिखा- पूरे प्रदेश के श्रमिकों, कामगारों की मजदूरी मई 2024 से पुनः कम होकर पुरानी दरों पर आ गई। इस पूरे प्रकरण में राज्य शासन का रवैया श्रमिक विरोधी प्रतीत होता है। उसमें तरफ से न हाईकोर्ट से स्टे हटवाने के संघर्षता से प्रयास किये गये न ही सुप्रीम कोर्ट में स्टे के खिलाफ याचिका लगाई गई। यही नहीं ब्रम अनुकूल ने 2014 की दरों से फूटान करने का आदेश जारी कर श्रमिकों के हितों पर फूटाववा किया है।

श्रमिकों के आंदोलन का समर्थन

दिविजय ने कहा, संवैधानिक प्रावधानों के तहत राज्य की अवधारणा एक लोक कल्याणकारी राज्य की है, जिसे जन-जन के व्यापक हित में निर्णय लेना चाहिये। न्यूनतम मजदूरी कम करने सरकार ने मजदूर विरोधी कदम उठाया है। अपने अग्रह है कि तत्काल मंत्रान लेते हुए कोर्ट से स्टे हटवाया जाये और मजदूरों की बढ़ी हुई दरों से भुगतान करने के निर्देश दिये जायें। शासन द्वारा न्यव न किये जाने पर कठिन घाटी श्रमिक संगठनों के आंदोलन का समर्थन करेगी।

Tax tribunals allow deductions for CSR donations

Lubna.Kably@timesgroup.com

Mumbai: Delhi and Mumbai benches of ITAT recently allowed a deduction under section 80-G of the I-T Act to two corporate entities for donations made by them, even though such donations were part of their CSR expenses.

During assessment, I-T officials had denied the deduction on the ground that donations, which are part of CSR expenses, are not voluntary in nature but are a compliance to be made under the Companies Act. Donations can only be voluntary in nature, was the stand taken by I-T officials.

Under section 135 of the Companies Act read with the rules, companies having a net

worth of Rs 500 crore or more, or turnover of Rs 1,000 crore or more, or net profit of Rs 5 crore or more have to comply with the CSR provisions. These companies have to spend at least 2% of their average net profit for the immediately preceding three financial years on CSR activities.

In the case of Alubound Dacs, which was heard by the Mumbai ITAT, a deduction of Rs 15 lakh made under 80-G for donations to educational and charitable trusts during the financial year 2019-20, was denied during assessment. The Delhi ITAT heard the case of Interglobe Technology Quotient, where during the financial year 2019-20, Rs 78 lakh was denied on the ground that the

Infant milk formula attracts GST at 18%

Mumbai: The GST-Authority for Advance Rulings (Rajasthan bench) has held that Bebymil was correctly levying and collecting GST at 18% against its infant milk formula products.

These products, which had variations based on age, were sold under the brand name of Momylac. The manufacturer approached the AAR as some competitors were charging GST only at 5%. The AAR held that Chapter 4 deals with milk products only. However, in the case of the applicant, milk was one of the constituents of Momylac. The product also contained cereals, protein supplements etc. Thus, the manufacturer had correctly computed GST at a higher rate. Tax experts emphasise that the classification norms need to become simpler. In the past, the Gujarat AAR bench has held lassi to be exempt from GST, but flavoured milk was held taxable at 12%. 7144

underlying expenditure was not in the nature of donation, but a mandatory CSR expense. Both companies succeeded in litigation at the ITAT level.

Nabli Ballodia, tax partner

at BDO-India, states, "This issue is a point of extensive litigation across India. However, tribunals are now increasingly allowing the deduction under section

80G. The reason for the allowance is that there is no embargo under section 80G to disallow the expenditure."

Sheetal Shah, partner EY-India, agrees, "Denial of deduction under section 80-G is a contentious issue for most companies, other than those who have opted for the concessional tax regime who cannot claim such a deduction. There is no express intent to deny deduction under section 80-G for all CSR expenditure, the law as it stands today does not indicate that govt is averse to tax benefits on CSR expenditure. Hence, a positive clarification from CBDT (giving clear directions to I-T officers) may avoid the disallowances and subsequent litigation."

"When you give joy to other people, you get more joy in return. You should give a good thought to happiness that you can give out."— Eleanor Roosevelt

NOTIFICATIONS/CIRCULARS**M.P. POWER MANAGEMENT COMPANY LIMITED**

CIN: U40109MP2006SGC018637 (A Government of MP Undertaking)
 Regd. Office: Shakti Bhawan, Rampur Jabalpur Madhya Pradesh INDIA 482 008. Tel: 0761-2661111,
 2660500, Fax: 0761 – 2661696, Website: www.mppmcl.com email: md@mppmcl.com

No. CGM (RM)/FPPAS/137

Jabalpur / Dated: 24/06/2024

To

1. The Managing Director
M.P. Paschim KVV Co. Ltd.
G.P.H Compound, Polo Ground, Indore (M.P)
2. The Managing Director
M.P. Madhya KVV Co. Ltd.
Bijli Nagar Colony, Nishtha Parisar, Govindpura, Bhopal (M.P)
3. The Managing Director
M.P. Poorv KVV Co. Ltd.
Block No.7 Ground Floor, Shakti Bhawan, Jabalpur (M.P)

Sub: - Fuel & Power Purchase Adjustment Surcharge (FPPAS) for the Month of June-2024

Ref: - First Amendment to MPERC (Terms and Conditions for Determination of Tariff for Supply and Wheeling of Electricity and Methods and Principles for Fixation of Charges) (1st Amendment) Regulation, 2021 (ARG-35(III) (i) of 2023)

As per the Regulations cited under reference, the FPPAS for the month of June-2024 has been calculated as 1.03 %. A detailed calculation sheet is attached herein for your reference.

Accordingly, FPPAS @ 1.03% is to be billed to the consumers on energy charge for one month commencing 24th June-2024. The FPPAS calculation along with the calculation sheet is to be uploaded on the website of the company to comply with the provisions of the Regulations.

Encl.: As above

(Shailendra Saxena)
Chief General Manager (RM)
MPPMCL JABALPUR

Copy to: -

1. OSD Energy, Deptt GoMP, Bhopal
2. The Secretary, MPERC, Metro Plaza, Bittan Market, Arera Colony, Bhopal
3. PS to MD.MPPMCL Jabalpur.
4. The Chief General Manager, Commercial (Conv.)/(Non-Conv.) MPPMCL
5. Chief Financial Officer, MPPMCL, Jabalpur
6. Director (Commercial) / CGM (Commercial) MPPoKVVCL/MPMaKVVCL/MPPaKVVCL, Jabalpur/Bhopal/Indore- A copy of FPPAS calculation sheet is enclosed for uploading on the Company's website.
7. The CGM (IT) MPPMCL, Jabalpur-
A copy of FPPAS calculation sheet is enclosed for uploading on the MPPMCL's website.

Chief General Manager (RM)
MPPMCL JABALPUR

Chief General Manager (Revenue Management) : Block no. 15, Ground floor, Shakti Bhawan, Rampur, Jabalpur 482008, Telephone no. Office:
 email:shailendra.saxena@mppmcl.com

NOTIFICATIONS/CIRCULARS**REVISION OF MINIMUM WAGES NOTIFICATION DATED 04.03.2024**

Minimum Wages has been revised by the MP Government through Notification dated 04.03.2024. The cases (WP No. No. 9401/2024, WP No. 10772/2024, 11921/2024 and 12606/2024) under this notification are pending before the High Court and stay (interim relief) in the said cases have been continued by the Honorable High Court vide order dated 01.07.2024.

1
IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
AT INDORE
WP No. 10772 of 2024
(MADHYA PRADESH TEXTILE MILLS ASSOCIATION Vs THE STATE OF MADHYA PRADESH AND OTHERS)
WP/09401/2024, WP/11921/2024, WP/12606/2024
WP-10772-2024
Dated : 01-07-2024

*Shri Girish Patwardhan- Senior Counsel with Ms Kirti Patwardhan -
Advocate for the petitioner.*

Shri Karpe Prakhar Mohan - Advocate for the respondent intervenor.

*Shri Bhuwan Gautam - Government Advocate for the respondents
State.*

Learned counsel for the respondent State prays for and is granted two weeks' time to file the reply.

Reply be filed positively within two weeks'.

List in the week commencing 22.07.2024.

I.R to continue, as per rules.

(S. A. DHARMADHIKARI)
JUDGE

(GAJENDRA SINGH)
JUDGE

mshmi



“It is only when we take chances, when our lives improve. The initial and the most difficult risk that we need to take is to become honest. —Walter Anderson

EVENTSWORLD ENVIRONMENT DAY

PLANTATION AT INDUSTRIAL AREA NO.1/SHANKAR GARGH –A plantation program was organized on the green Belt situated in the front of Khanuja Wood Works by **M/s Cummins Turbo Technologies**. Similarly, plantation program was also organized at Shanker Gargh by the **M/s Sun Pharmaceutical Industries Limited**. The Collector Dewas and other dignitaries Participated in the plantation program.



“I never dreamed about success. I worked for it.” —Estée Lauder

EVENTS

“NIDHI APKE NIKAT 2.0”

“Nidhi Apke Nikat 2.0” program was organized by RPFC at **Jila Panchayat Karyalaya (Conference Hall) near MG Hospital Dewas** on 27.06.2024.

In this program, the problems related to KYC/ Full & final/ Pension of employers and the employees were resolved.



“Concentrate all your thoughts upon the work in hand. The sun's rays do not burn until brought to a focus.” — Alexander Graham Bell


WITH BEST COMPLIMENTS FROM:



HYDRAULIC HAND PALLET TRUCK



Features



Integrated Pump With Hydraulic Pump. Entry/exit Rollers Provide Smooth Pallet Access & Increased Productivity.



End Cap Connected With The Lifting Cylinder, Shorter & Stronger



Ergonomic Handle To Provide Comfortable & Efficient Operation



Solid Frame & Reinforced Fork Ensures High Reliability



Standard Nylon Wheel & Optional PU Wheels Are Available



More Stable & Stronger Chassis Design. Fork Roots are enclosed by welding.

Other Products : - ■ Racking System ■ Mezzanine Floor ■ Compactors ■ Pallets ■ Bins

DEWAS TECHNO PRODUCTS PVT. LTD. | © +91 9752497382 | info@giraffestorage.com | www.giraffestorage.com/HPT